INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

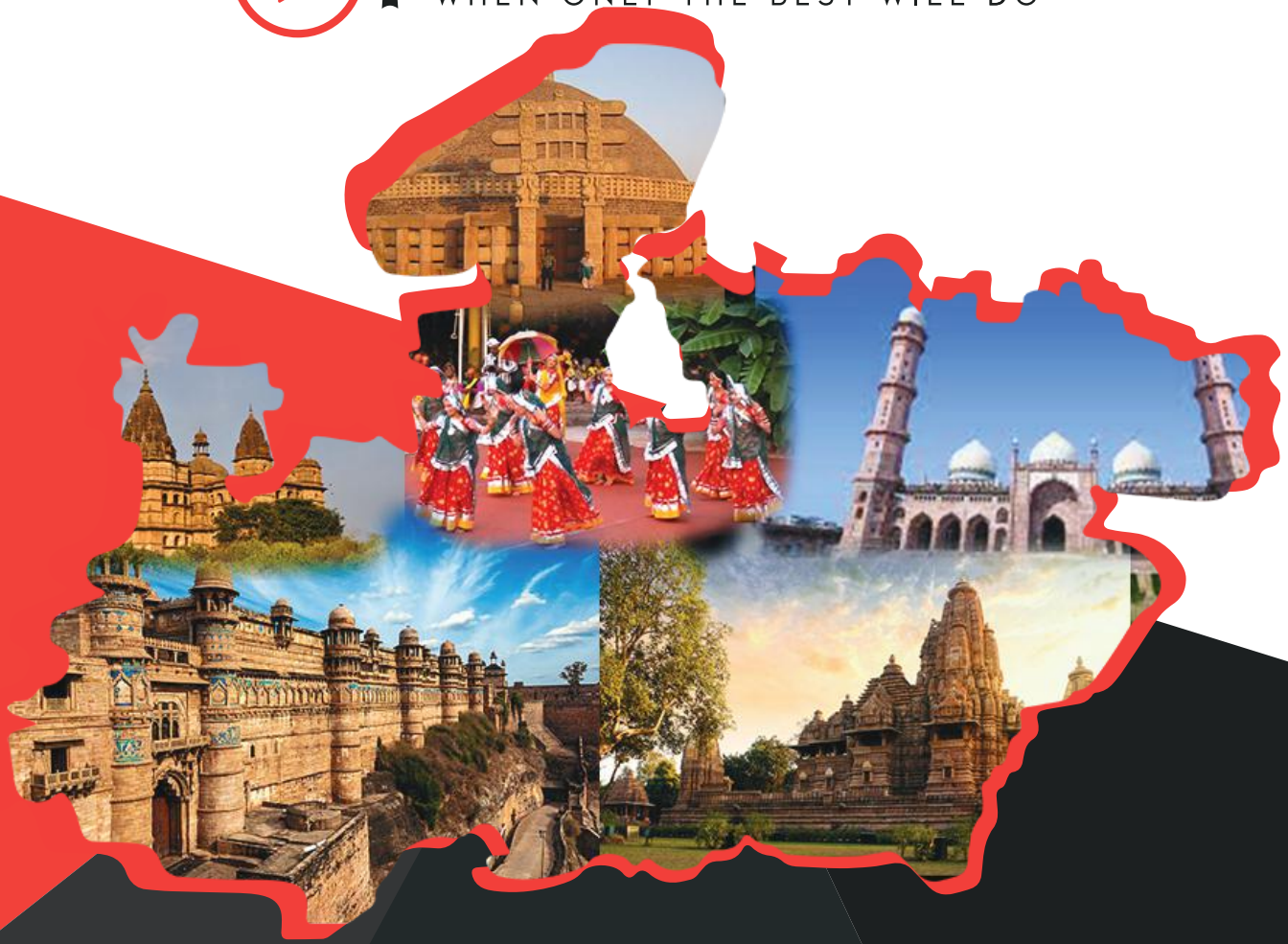

MPPSC-PCS

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

HANDWRITTEN NOTES

भाग -4 भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

MPPSC-PCS

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 4

भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"MPPSC -PCS (Madhya Pradesh Public Service Commission) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)"** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/dy0fu7

Online Order करें - https://bit.ly/3BGkwhu

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम (2023)**

भारतीय अर्थव्यवस्था		
क्र.सं.	अध्याय	पेज
1.	अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणायें • परिचय • अर्थव्यवस्था के प्रकार • अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक	1-5
2.	बजट एवं बजट निर्माण • बजट • बजट के प्रकार • बजट निर्माण प्रक्रिया • बजट निर्माण के सिद्धांत • वित्त घाटे के प्रकार • बजट से संबंधित वैधानिक कोष • जीरो बेस बजट • जेंडर बजटिंग • बजट 2023-24	6-18
3.	बैंकिंग • सिक्कों का उत्पादन • औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना • ऋणदर का सीमांत लागत • बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास • भारत में बैंकों का वर्गीकरण • भारतीय औद्योगिक विकास बैंक • भारत में विदेशी बैंक • बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियाँ • बैंक बोर्ड ब्यूरो	19-43

	• भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से सम्बंधित नियम • भारत में भुगतान प्रणाली	
4.	वस्तु एवं सेवा कर • GST के प्रकार • GST में कर की दरें • GST का आम लोगों पर प्रभाव	44-48
5.	राष्ट्रीय आय • सकल घरेलू उत्पाद • शुद्ध घरेलू उत्पाद • सकल राष्ट्रीय उत्पाद • शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद • राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ • हरित राष्ट्रीय आय • हरित GDP • राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ	49-57
6.	संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान • आर्थिक विकास • आर्थिक संवृद्धि • मानव विकास रिपोर्ट-2019	57-59
7.	स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार • शेयर बाजार में निवेशकों के प्रकार • शेयर वारंट • स्टॉक एक्सचेंज • सक्रिय शेयर	59-65

8.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ • राजकोषीय नीति की परिभाषा • मौद्रिक नीति की परिभाषा	66-69
9.	ई-कॉमर्स • ई-कॉमर्स का इतिहास • ई-कॉमर्स का प्रकार • ई-कॉमर्स के फायदें • ई-कॉमर्स का नुकसान • ऑनलाइन मार्केटप्लेस • ई-कॉमर्स के संबंध में सरकारी प्रयास	70-75
10.	कृषि • कृषि के अन्य प्रकार एवं प्रतिरूप • भारत की फसल ऋतुएँ • प्रमुख फसलें • हरित क्रान्ति	76-84
11.	औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां • औद्योगिक नीति • भारत में औद्योगिक नीति का विकास • औद्योगिक नीति, 1948, 1956, 1991 • औद्योगिक वित्त • प्रमुख उद्योग • आर्थिक सुधार • अवसरंचना एवं आर्थिक वृद्धि • मानव विकास रिपोर्ट-2022	84-106
12.	भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र • औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	107-108

	• भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ • भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये प्रमुख सरकारी पहलें	
13.	आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका • पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र • नीति आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम	108-112
14.	आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहलें • भारत में पंचवर्षीय योजना • योजना आयोग का इण्डिया विजन, 2020 • पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र	112-119
15.	मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना • जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन • मध्य प्रदेश जनसंख्या निति 2000 , • मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का प्रभाव • मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम	120-125
16.	मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास • राज्य का आर्थिक वर्गीकरण • मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग • मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ • मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल • मध्य प्रदेश की योजनाएँ एवं कल्याणकारी कार्यक्रम	125-158

अर्थशास्त्र

अध्याय – I

अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणायें

परिचयः-

- Economics (अर्थशास्त्र) शब्द एक Greek word ' Oikonomia ' से उत्पन्न हुआ है ।
- Oikonomia शब्द Oikos and Nomos दो शब्दों से मिलकर बना है ।
- Oikos का अर्थ गृह अथवा परिवार जबकि Nomos का का अर्थ है प्रबंधन । अर्थात् Oikonomia गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है ।

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर?:-

अर्थशास्त्र	अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है	अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है	अर्थव्यवस्था निष्पादन (Execution) की भूमिका निभाती है।
अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है इनकी किताब (The Wealth of nations) मे अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है।	जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं ।
अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं- (i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics) (ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)	अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
	अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यावहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि ।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economic)

- अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)
(ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

अर्थव्यवस्था के प्रकारः-

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy):-

- जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
- अर्थात् यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है।
- एडम स्मिथ की 'दा वेल्थ ऑफ़ नेशन' पूँजीवाद को दार्शनिक आधार प्रदान करता है।
- अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोपीय देश पूँजीवाद के समर्थक हैं।

पूँजीवाद के फायदे या गुणः-

- पूँजीवाद नवाचार को बढ़ावा देता है।
- पूँजीवाद और समाज दोनों स्वतंत्रता और अवसर पर केंद्रित हैं।
- पूँजीवाद आबादी की जरूरतों को पूरा करता है।
- पूँजीवाद स्व-नियामक है।
- पूँजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद करता है।

पूँजीवाद के नुकसान या दोषः-

- धन और आय के वितरण की असमानता
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य के रूप में कक्षा संघर्ष
- सामाजिक लागत बहुत अधिक है
- पूँजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता
- बेरोजगारी और रोजगार के तहत

- वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है ।

B. समाजवाद अर्थव्यवस्था

- उत्पादन एवं वितरण के सामूहिक नियंत्रण पर बल देता है।
- राज्य द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र की भूमिका से लोक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति।
- भारत,बांग्लादेश,ब्राजील,समेत विकासशील अधिकांश देश समाजवाद के समर्थक हैं।
- बौद्ध और जैन धर्म का अस्तेय आवश्यकता से अधिक संसाधनों के एकत्रीकरण का विरोध करता है, जो समाजवाद की अवधारणा के अनुकूल है।
- अशोक के शिलालेखो से लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती हैं, वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में प्रमाण देता है।
- इसी प्रकार मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण, बेरोजगारों के लिए पेंशन जैसी समाजवादी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

समाजवाद के पक्ष में तर्क या गुण:-

शोषण का अन्त:-

- समाजवाद श्रमिको एवं निर्धनो के शोषण का विरोध करता है। इसलिये विश्व के श्रमिक किसान निर्धन इसका समर्थन करते है।

सामाजिक न्याय पर आधारित:-

- समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष के हितो को महत्व न देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितो को महत्व दिया जाता है यह व्यवस्था पूँजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक ऐसे वर्गविहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन करती है जिसमें विषमता न्यूनतम हो।

उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यक्ता:-

- व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किये जाने वाले उत्पादन के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था में समाजिक आवश्यक्ता और हित को ध्यान में रखकर उत्पादन होगा क्योंकिसमाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन हो वह समाज के बहुसख्यक लोगो के लाभ के लिए हो।

उत्पादन पर समाज का नियंत्रण :-

- समाजवादियो का मत है कि उत्पादन और वितरण के साधनो पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करके विषमता को समाप्त किया जा सकता है।
- सभी को उन्नति के समान अवसर
- साम्राज्यवाद का विरोधी

समाजवाद के विपक्ष में तर्क अथवा आलोचना :-

राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि :-

- समाजवाद मे आर्थिक तथा राजनीतिक दोनो क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्य समुचित रूप से संचालित और समपादित नहीं होंगे।

वस्तुओं के उत्पादन में कमी :-

- समाजवाद के आलोचको की मान्यता है कि यदि उत्पादन के साधनो पर सम्पूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी और कार्यक्षमता भी धीरे धीरे घट जायेगी।
- व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा तो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घट जायेगी।

समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी :-

- प्रजातंत्र में व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है वही समाजवाद में वह राज्य रूपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पूर्जा बन जाता है।

नौकरशाही का महत्व :-

- समाजवाद में राज्य के कार्यो में वृध्दि होने के कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ता है। और सभी निर्णय सरकारी कर्मचारियो द्वारा लिये जाते है ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ता है।

समाजवाद हिंसा को बढ़ाता है :-

- समाजवाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी तथा हिंसात्मक मार्ग को अपनाता है। वह शांतिपूर्ण तरीको में विश्वास नहीं करता।
- वह वर्ग संघर्ष पर बल देता है। जिसके परिणामस्वरूप समाज में वैमनस्यता और विभाजन की भावना फैलती है।
- पूर्ण समानता संभव नहीं ।

C. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) :-

- यहाँ, उत्पादन की कुछ योजनाएँ राज्य द्वारा सीधे या इसके राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से शुरू की जाती है, और कुछ को निजी उद्यम के लिए छोड़ दिया जाता है।
- इसका अर्थ है कि समाजवादी क्षेत्र (यानी सार्वजनिक क्षेत्र) और पूँजीवादी क्षेत्र (यानी निजी क्षेत्र) दोनों एक-दूसरे के साथ हैऔर एक-दूसरे के पूरक हैं।
- इसे बाजार की अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच आधे घर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। इसलिए, इस प्रकार कीअर्थव्यवस्था पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे:-

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन :-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करता है और इसे बढ़ने का उचित अवसर मिलता है।
- यह देश के भीतर पूँजी निर्माण में वृद्धि की ओर जाता है।

स्वतंत्रता:-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक और व्यावसायिक दोनों तरह की स्वतंत्रता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है।
- इसी तरह, हर निर्माता उत्पादन और खपत के संबंध में निर्णय ले सकता है।

संसाधनों का इष्टतम उपयोग:-

- इस प्रणाली के तहत, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए काम करते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक लाभ के लिए काम करता है जबकि निजी क्षेत्र लाभ के अधिकतम करण के लिए इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है।

आर्थिक योजना के लाभ:-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, आर्थिक योजना के सभी फायदे हैं।
- सरकार आर्थिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और अन्य आर्थिक बुराइयों को पूरा करने के लिए उपाय करती है।

कम आर्थिक असमानताएँ:-

- पूँजीवाद आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है लेकिन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत, सरकार के प्रयासों से असमानताओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

प्रतियोगिता और कुशल उत्पादन:-

- निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण दक्षता का स्तर उच्च बना हुआ है।
- उत्पादन के सभी कारक लाभ की उम्मीद में कुशलता से काम करते हैं।

सामाजिक कल्याण:-

- इस प्रणाली के तहत, प्रभावी आर्थिक, योजना के माध्यम से सामाजिक कल्याण को मुख्य प्राथमिकता दी जाती है।
- सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है।
- निजी क्षेत्र की उत्पादन और मूल्य नीतियां अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए निर्धारित की जाती हैं।

आर्थिक विकास:-

- इस प्रणाली के तहत, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के विकास के लिए अपने हाथ मिलाते हैं, इसके अलावा, सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कई विधायी उपाय लागू करती है।
- इसलिए, किसी भी अविकसित देश के लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था सही विकल्प है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के नुकसान:-

स्थिरता:-

- कुछ अर्थशास्त्रियों का दावा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अस्थिर है।
- सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकतम लाभ मिलता है जबकि निजी क्षेत्र नियंत्रित रहता है।

क्षेत्रों की अक्षमता:-

- इस प्रणाली के तहत, दोनों क्षेत्र अप्रभावी हैं।
- निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती है, इसलिए यह अप्रभावी हो जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2002-03 में ऐसे ही बजट का मूल्यांकन कई राज्यों द्वारा किया गया था ।
- 2003 में कैबिनेट सचिव के आदेशानुसार प्रत्येक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विभाग को यह निर्देश दिया गया कि अपने वार्षिक रिपोर्ट में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से किए गए प्रयासों को एक भिन्न खंड के अंतर्गत प्रकाशित करें वर्ष 2004 में वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया कि सभी मंत्रालयों में जनवरी , 2005 तक एक जेंडर बजटिंग सेल होना चाहिए । यह जेंडर बजटिंग सेल उन कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन हेतु जिम्मेदार होता है जो 100 % महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है । साथ ही यह उन कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन हेतु भी जिम्मेदार होता है , जिनके कम से कम 30 % प्रावधान महिला उत्थान के लिए हों । अत : जेंडर बजटिंग देश में सामाजिक न्याय की स्थापना का एक उपकरण बन गया है ।

रेल बजट एवं आम बजट का विलय

- वर्ष 1924 से पूर्व रेल बजट एवं आम बजट दोनों साथ प्रस्तुत किए जाते थे ।
- हालांकि इस आम बजट में रेलवे की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के अन्य आयामों की प्राप्तियों एवं व्यय से कहीं ज्यादा हुआ करती थी । इस दौरान रेलवे का बजट में व्यापक योगदान सरकार की कमियों को उजागर होने से रोकता था ।
- अतः पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे आयोग का गठन किया गया ।
- 1920 में गठित इस आयोग की संस्तुति के आधार पर 1924 में आम बजट एवं रेल बजट को पृथक् कर दिया गया आजादी के बाद स्थिति की पुन : समीक्षा की गई ।
- आम बजट एवं रेल बजट को अलग - अलग प्रस्तुत करने की यह प्रक्रिया 92 वर्षों तक जारी रही और अंततः बजट 2017-18 में इन दोनों का विलय कर दिया गया ।

बजट 2023-24

2023-24 का बजट अनुमान

- कुल प्राप्तियां (उधारी के अलावा)- 27.2 लाख करोड़
- कुल व्यय - 45 लाख करोड़
- नेट टैक्स प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़

बजट 2023 की खास बातें

- भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 रु. हुई।
- अगले एक साल तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी।
- पीएम सुरक्षा के तहत् 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा।
- बागवानी योजनाओं पर रहेगा जोर, 2200 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान।
- कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड रुपए किया जाएगा।
- 157 नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग हिस्सों में खोले जाएंगे।
- अनुसूचित जाति मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ खर्च होंगे।
- पीएम आवास योजना फंड में 66 फ़ीसदी की बढ़ोतरी।

बजट 2023 में क्या हुआ सस्ता और महंगा?

- सस्ता - इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, साइकिल, लिथियम बैटरी, हीरे के आभूषण।
- महंगा:- सोना, आयातित चाँदी, प्लेटिनम, विदेशी किचन चिमनी, सिगरेट।

Note:- 2023-24 का बजट अमृत काल में पहला बजट है।

- बजट: व्यय, कर, लेन- देन और योजनाओं का ब्लूप्रिंट है।
- संविधान के अनुच्छेद- 112 में बजट शब्द का उपयोग न करते हुए इसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है।
- यह बजट आगामी वर्ष 2023- 24 के लिए पेश किया गया है।
- वर्ष 2022- 23 में भारत की विकास दर 7% के आस-पास रही है, जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसी महामारी कोविड-19 और वैश्विक मंदी जो रही है।

- वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा गया था। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रही है।
- वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9 प्रतिशत रखा गया है और इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है ।
- वर्ष 2023-24 का बजट 7 मूल आधारों पर आधारित है, जिसे सप्त ऋषि- 7 कहा गया है।
  1. समावेशी विकास - (a)कृषि (b)स्वास्थ्य क्षेत्र (c)शिक्षा क्षेत्र
  2.वित्तीय क्षेत्र
  3.युवा शक्ति
  4.आखिरी व्यक्ति तक पहुंच
  5. अवसंरचना निवेश
  6. सक्षमता का विकास
  7. हरित विकास

  कृषि और सहकारिता:- ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि
- उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम
- भारत को श्री अन्न देने के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
- पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य।
- भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग।
- भारत मिलेट (बाजरा) को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है।

❖ ***स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि:-*** वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत।

- वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए ***उन्मूलन मिशन*** की शुरुआत।
- चुने हुए ICMR लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सीय अनुसंधान को प्रोत्साहन।
- फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत।

❖ ***<u>आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना</u>*** : "कोई पीछे न छूटे"

- प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत।
- कर्नाटक के सूखा संभाव्य क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता।
- 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 से अधिक शिक्षकों की भर्ती।
- PMGKAY के तहत्, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
- प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए 'भारत श्री' योजना की शुरुआत।
- पीएम- आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि।

<u>अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश</u> :-

<u>विकास व रोजगार के अवसरों में वृद्धि</u>:

- पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया।
- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, अवसंरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हित धारकों की सहायता करेगा।
- UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी- 2 और श्रेणी- 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन।
- राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा।

Note- अमृत काल के लिए ***संकल्पना:*** "सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था"

- इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  1. नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।
  2. विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना।
  3. वृहद् आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना।

❖ ***अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं -***

1. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:
2. पीएम- विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)
3. पर्यटन
4. हरित विकास

❖ ***<u>अध्यापकों का प्रशिक्षण</u>:-*** नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत् पेशेवर विकास, डिपास्तिक सर्वेक्षण और आईसीटी

अध्याय - 3

बैंकिंग

- बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता की धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है।
- लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं।
- बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं।

भारत में बैंकिंग

- भारत में स्थापित पहली बैंक Bank of Hindustan थी इसकी स्थापना Alexandey and Company 1770ई. में की थी कुछ समय बाद यह बैंक बन्द हो गई।
- इसके बाद देश में निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना की गई - वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल (Bank of Bengal.) , वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे (Bank of Bombay) तथा वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास (Bank of Madras) ।
- इन तीनों बैंकों पर बैंक ऑफ मद्रास अपना नियंत्रण रखती थी । बाद में इन बैंकों के कार्यों को सीमित कर दिया गया । वर्ष 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Impe rial Bank of India) की स्थापना की गई और। जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया ।
- भारत में पहली सीमित देयता वाला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था जिसकी स्थापना फैजाबाद में वर्ष 1881 में की गयी थी ।
- उसके बाद वर्ष 1894 में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई जो पहला पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था ।

भारत में स्थापित प्रमुख बैंक व उनकी स्थापना

बैंक का नाम	स्थापना वर्ष
द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
बैंक ऑफ बंगाल	1806
बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
बैंक ऑफ मुद्रास	1843
इलाहाबाद बैंक	1865
एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला	1881
अवध कॉमर्शियल बैंक	1881
पंजाब नेशन बैंक	1894
बैंक ऑफ इंडिया	1906
पंजाब एंड सिंध बैंक	1908
बैंक ऑफ बडौदा	1909
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1911
बैंक ऑफ मैसूर	1913
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया	1921
भारतीय रिजर्व बैंक	1935
भारतीय स्टेट बैंक	1955

भारतीय रिजर्व बैंक

- भारत का केन्द्रीय बैंक है ।
- वर्ष 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (R.B.I.) की स्थापना RBI अधिनियम, 1934 के तहत् । अप्रैल , 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से हुई थी ।
- 1 जनवरी, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ (1935-37) थे ।
- देश के स्वतंत्रता के समय में RBI के गर्वनर सर सी डी . देशमुख (1943-49) थे ।
- रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Borad of Directors) द्वारा होता है ।
- सम्पूर्ण देश में इसे चार भागों में बाँटा गया है - उत्तरी क्षेत्र , दक्षिणी क्षेत्र , पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र ।

साख नियंत्रण (Control of Credit)

- रिजर्व बैंक साख के नियंत्रण एवं नियमन हेतु दो प्रकार के का प्रयोग करता है
  (A) परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण
  (B) गुणात्मक साख नियंत्रण

- इनके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रा पूर्ति / साख को प्रभावित किया जा सकता है । इनके द्वारा साख के प्रवाह को न तो अर्थव्यवस्था के किसी खास क्षेत्र की ओर निर्देशित किया जाता है और न ही सीमित किया जाता है । ये विधियाँ निम्न हैं-

(A) परिमाणात्मक विधियाँ

बैंक दर (Bank Rate)	• भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यावसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, बैंक दर कहलाता है । • **प्रभाव-** बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों द्वारा आवंटित ऋणों की ब्याज दर पर पड़ता है । इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों की कुल वैधानिक जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर उनके मूल कोटे निर्धारित कर दिया गया । • निर्धारित कोटे की सीमा तक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण लिया जा सकता है । इससे अधिक ऋण देने पर बैंक दर के अतिरिक्त ब्याज की दंड दर (Penal rate) देनी पड़ती है । • बैंक दर में वृद्धि या कमी व्यावसायिक बैंक द्वारा आवंटित ऋणों पर ब्याद दर कम या ज्यादा करने के लिए होता है । • **NOTE :** बेस रेट वह दर है जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी भी तरह का ऋण नहीं दे सकते हैं । यह वर्ष 2010 में पूर्व प्रचलित प्राइम लैंडिंग रेट नोट (PLR) के स्थान पर अपनाया गया है
नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio)	• प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी कुछ जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास सदैव नकद रूप में रखता है जिसे नकद आरक्षण अनुपात (CRR) कहते हैं । • रिजर्व बैंक इस नकद पर कोई ब्याज बैंक को नहीं देता है । जब रिजर्व बैंक साख मुद्रा वृद्धि करना चाहता है , तो वह इस अनुपात में कमी कर देता है । और यदि वह साख मुद्रा में कमी करना चाहता है , तो वह इस अनुपात में वृद्धि कर देता है ।
वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)	• प्रत्येक बैंक को कुल जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसम्पत्तियों के रूप में (सोना अनुमोदित प्रतिभूतियाँ- सरकारी प्रतिभूतियाँ) रखना पड़ता है जिसे वैधानिक तरलता (SLR) कहा जाता है । • यदि रिजर्व बैंक को साख मुद्रा का प्रसार करना होता है , तो इस अनुपात को कम कर दिया जाता है , ताकि बैंकों के पास तरल कोषों में वृद्धि हो सके । • यदि साख का संकुचन करना होता है , तो इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता है , ताकि बैंकों के पास तरल कोष कम उपलब्ध हो ।
रेपो दर (Repo Rate)	• रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है । • इसका प्रभाव व्यावसायिक बैंकों द्वारा आवंटित ऋणों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है ।

	• इसका प्रयोग तात्कालिक मुद्रा के प्रसार में वृद्धि या कमी के लिए किया जाता है । • मंदी के दौरान रेपो दर में कटौती की जाती है ताकि मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हो । ज्यों - ज्यों मंदी का दौर खत्म होता है , रेपो दर से वृद्धि की जाती है ताकि तात्कालिक मुद्रा का प्रसार कम हो ।
रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)	• यह रेपो दर से उल्टी होती है । बैंकों के पास दिनभर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है । बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाए रिजर्व बैंक में रख सकते हैं , जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है । जिस दर पर यह ब्याज मिलता उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं ।
मार्जिनल स्टैंण्डिंग फैसिलिटी (MSF)	• इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक । दिन (24 घण्टे) हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं । • MSF के माध्यम से बैंक अपनी NDTL के 2.5% तक ऋण प्राप्त कर सकते है । • इसमें SLR में रखी प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकते है । • यह सुविधा मात्र वाणिज्यक बैंकों को उपलब्ध है । MSF की ब्याज दर Repo rate से 0.25 % अधिक होती

NOTE- खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Opera tions)

- खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केन्द्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण - पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है । केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है , जिससे साख का सन्तुलन होता है और प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा साख का विस्तार हो जाता है ।
- तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियों एवं ऋणों का अनुक्रम है – नकद, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स (इन्हें बंद किया जा चुका है), ट्रेजरी बिल्स तथा कॉल मनी।

ऋणदर का सीमांत लागत (MCLR)

- यह अप्रैल, 2016 में प्रभावी हुआ ।
- यह फ्लोटिंग - रेट ऋणों के लिये एक बेंचमार्क ऋण दर है ।
- यह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं ।
- यह दर चार घटकों- धन की सीमांत लागत, नकद आरक्षित अनुषात, परिचालन लागत और परिपक्वता अवधि पर आधारित है ।
- MCLR वास्तविक जमा दरों से जुड़ा हुआ है । इसलिए जब जमा दरों में वृद्धि होती है तो यह इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है ।
- इसका उद्देश्य RBI द्वारा किए गए परिवर्तन का लाभ बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है ।

(B) गुणात्मक विधियाँ

- इन विधियों द्वारा साख के प्रवाह को आर्थिक क्रिया के निर्दिष्ट या विशेष क्षेत्र की ओर मोड़ते या सीमित करते हैं ।
- गुणात्मक विधियों कुछ सीमा तक परिमाणात्मक विधियों का भी अश रहता है ।
- ये विधियाँ निम्न है –

I. सीमांत आवश्यकता (Margin Requirement)

: सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से है । जैसे- मान लीजिए किसी व्यक्ति ने100रु. मूल्य का माल बैंक के पास जमानत के रूप में रखा है और बैंक उसे 80रु. का ऋण देता है । इस स्थिति में सीमांत आवश्यकता 20% होगी । यदि अर्थव्यवस्था की किसी विशेष व्यावसायिक क्रिया के लिए साख के प्रवाह को सीमित करना है तो उस क्रिया के लिए सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाएगा । इसके

के उद्देश्य से समाज के निम्न वर्ग को भी बैंकिंग व्यवस्था से भी जोड़ने के उद्देश्य से एवम् जमाकर्ता के हितों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया ।

- बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन का मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों (जिनकी जमाएँ 50 करोड़ रु से अधिक थीं) का राष्ट्रीयकरण कर दिया ।
- ये बैंक थे-

1. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
2. पंजाब नेशनल बैंक
3. बैंक ऑफ इण्डिया
4. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
5. सिण्डीकेट बैंक
6. केनरा बैंक
7. बैंक ऑफ बड़ौदा
8. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
9. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
10. इलाहाबाद बैंक
11. देना बैंक
12 इण्डियन बैंक
13 इण्डियन बैंक
14 बैंक ऑफ महाराष्ट्र को सरकार

भारत में बैंकों का वर्गीकरण

भारत में बैंकों को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता

1. अनुसूचित बैंक (scheduled Bank)
2. गैर अनुसूचित बैंक (Non scheduled Bank)

Non- Scheduled Bank, RBI की अनुमति के बिना भी स्थापित हो जाती हैं एवम् इसका संचालन भी RBI नहीं करती इससे भिन्न अनुसूचित बैंक, RBI की अनुमति से स्थापित होती हैं एवम् इनका संचालन RBI करती हैं, अनुसूचित बैंक वह बैंक हैं जो RBI अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सूचिबद्ध हैं इन बैंको को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होता है |

1. इनकी किसी भी क्रिया से ग्राहकों को क्षति नहीं पहुंचरी चाहिए
2. इनकी यूनतम प्रक्षप्त पूंजी 5 lakh रु की होनी चाहिए। (इसे बढ़ाकर RBI ने 500cr कर दिया हैं) प्रदप्त पूँजी वह पूंजी हैं जो की एक कम्पनी का संस्थापक एवम् अन्य शेष धारक उस कंपनी की स्थापना में निवेश करते हैं
3. उन बैंकों को RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीतियों का अनुपालन करना होता हैं आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक RBI से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं

- विश्व की सबसे बड़ी Bank. I.P Mangon Chese हैं यह एक अमेरीकी बैंक हैं परन्तु भारत में यह बैंकिंक सेवाएँ नहीं प्रदान करती भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में सबसे बड़ी बैंक HSBC हैं जिसका मुख्यालय लंदन में हैं
- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में सर्वाधिक शाखाएँ stancdland chailed बैंक की हैं यह भी एक Boilish Bank हैं
- कुल परिसंपत्ति के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी बैंक JCBC हैं
- बाजारी पूंजीकरण के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक HDFC Bank हैं परन्तु शाखाओं के आधार पर लाभ के आधार पर एवम् के आधार पर SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक हैं।
- परिसंपत्ति के आधार पर SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक हैं
- Rupco Bank जो की एक सहकारी Bank हैं, भारत की एक मात्र ऐसी बैंक हैं जो गृहमंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत हैं

भुगतान बैंक (Payments Bank)

- बैंकिंग सेवाओं में विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त, 2015 को भुगतान बैंकों को सैद्धान्तिक मंजूरी दी ।
- वर्ष 2014-15 के आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विशिष्ट प्रकार के बैंक की बात की थी जो क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय लोगों के निजी हितों का ध्यान रखते हुए बैंकिंग करेंगे ।
- भुगतान बैंकों की विशेषताएँ हैं-

i. खाताधारक रु 1 लाख तक की धनराशि जमा कर सकेंगे ।

ii. ATM डेबिट कार्ड जारी कर सकेंगे , लेकिन क्रेडिट कार्ड कर सकेंगे ।

iii. पैसों का लेन - देन किया जा सकेगा ऋण नहीं दे सकेंगे ।

iv. केवल नकदी व सरकारी प्रतिभूतियाँ ही जमा कर सकेंगे ।

- वाणिज्यिक बैंकों की तरह यह भी CRR के रूप में 4% की राशि रखेंगे
- कुल जमा राशि का कम से कम 75% हिस्सा SLR के रूप में रखनी होगी जो कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में होगी ।
- अतिरिक्त आय के लिए यह बैंक बीमा कम्पनियों के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं बेंच सकती है साथ ही Mutual fund योजनाएं भी बेच सकती हैं ।
- वर्ष 2013 में RBI ने पेमेण्ट बैंक (भुगतान बैंक) के लिए पेपर जारी किया था ।

- इसके बाद नचिकेत मोर कमेटी गठित कर RBI ने 11 कम्पनियों को पेमेण्ट बैंक के लाइसेन्स इनमें शामिल हैं- एयरटेल, वोडाफोन, आदित्य बिरला ग्रुप मण्डलम, टेक महिन्द्रा रिलायन्स तथा भारतीय डाक विभाग ।
- जिन मोबाइल टेलीफोन कम्पनियों और सुपर बाजार श्रृंखला के स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीयों के पास हैं वे भुगतान बैंक से हो सकते हैं ।
- भुगतान बैंक के लिए इक्विटी कैपिटल की सीमा न्यूनतम होनी चाहिए । इसका प्रसार क्षेत्र पूरे भारत में हो सकता है ।

लघु वित्त बैंक

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छोटे किसानों और कुटीर उद्योगों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 16 सितम्बर, 2015 को 10 कम्पनियों को लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक मजूरी दी ।
- लघु वित्त बैंक छोटे किसानों कुटीर उद्योग , लघु और अतिलघु एवं असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाएँगे ।
- इन बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में कम - से - कम 50 % योगदान ₹ 25 लाख तक के ऋण और अग्रिमों का होना अपरिहार्य है ।

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेन्स एजेंसी (मुद्रा) बैंक

- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाईनेन्स एजेन्सी (मुद्रा) बैंक 2015 के बजट में की गई है जिसके लिए ₹ 20,000 करोड़ निर्धारित किया गया है और इसमें ₹ 3,000 करोड़ की ऋण राशि की घोषणा की गई है ।
- मुद्रा बैंक **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के जरिए सूक्ष्म वित्त संस्थान पुनर्वित्तीयन करेगा तथा कर्ज देते समय अनुसूचित जाति / जनजाति को प्राथमिकता दी जाएगी ।
- इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ₹ 50 हजार से ₹ 10 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा । इस व्यवस्था के तहत तीन तरह के ऋण दिए जाते हैं

  (i) शिशु ऋण- ₹ 50.000 तक के ऋण हेतु

  (ii) किशोर ऋण- ₹ 50,000 से अधिक तथा ₹ 5 लाख तक

  (ii) तरुण ऋण- ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक

भारतीय महिला बैंक लिमिटेड

- उद्घाटन-19 सितंबर , 2013
- प्रारंभिक पूँजी- 1000 करोड़
- स्थापना - मुम्बई मुख्यालय- नई दिल्ली
- स्वरूप- समाज में महिलाओं को समान अवसर देने और उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतमें प्रथम बैंक की नींव रखी ।
- उद्देश्य- सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वित्तीय सुविधाओं को सुगम बनाना , महिलाओं का सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन । आर्थिक सशक्तीकरण के लिये महिलाओं को आर्थिक संस्थाओं और परिसंपत्तियों पर नियंत्रण की समान सुविधाएँ प्रदान करना ।
- पाकिस्तान और तंजानिया के पश्चात् भारत ऐसा तीसरा देश है जिसने महिलाओं के लिए विशेष बैंक स्थापित किया है । 31 मार्च, 2017 को भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया है ।

Islamic Bank

- इस्लामिक Bank एक NBFC के रूप में कार्य करती हैं चूंकि यह इस्लामिक नियमों का अनुपालन करती हैं ।
- यह ऐसे किसी भी क्रिया से सम्बंध नहीं रखेगी जो की इस्लाम में हराम माना गया हो ।
- दुनिया भर में पहला इस्लामिक बैंक मलेशिया में वर्ष 1983 में स्थापित हुआ था।
- भारत में सबसे पहला इस्लामिक बैंक वर्ष 2011 में केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोच्ची (केरल) में स्थापित किया गया जिसका नाम Charraman Financial services Limited है।

अध्याय – 8

राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ

राजकोषीय नीति की परिभाषा

जब किसी देश की सरकार देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लिए समग्र मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए अपनी कर राजस्व और व्यय नीतियों को लागू करती है, तो इसे राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। यह सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से खर्च करने और विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च करने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है। किसी देश की राजकोषीय नीति की घोषणा प्रत्येक वर्ष बजट के माध्यम से वित्त मंत्री द्वारा की जाती है।

यदि राजस्व व्यय से अधिक है, तो इस स्थिति को राजकोषीय अधिशेष के रूप में जाना जाता है, जबकि यदि व्यय राजस्व से अधिक है, तो इसे राजकोषीय घाटे के रूप में जाना जाता है। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य स्थिरता लाना, बेरोजगारी को कम करना और अर्थव्यवस्था का विकास करना है। राजकोषीय नीति में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कराधान और इसकी संरचना और विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय का स्तर हैं। राजकोषीय नीति के दो प्रकार हैं, वे हैं:

- **विस्तारवादी राजकोषीय नीति** : वह नीति जिसमें सरकार करों को कम करती है और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है।
- **संविदात्मक राजकोषीय नीति** : वह नीति जिसमें सरकार कर बढ़ाती है और सार्वजनिक व्यय को कम करती है।

- राजकोषीय नीति को निम्न निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है: -

I. संसाधनों के सही उपयोग द्वारा विकास करना : राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करना और उसे बनाये रखना है। आर्थिक वृद्धि के इस उद्देश्य को वित्तीय संसाधनों के सदुपयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें संसाधन जुटाने के लिए राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करते हैं।

वित्तीय संसाधनों को निम्न प्रकार जुटाया जा सकता है: -**a. कराधान:** प्रभावी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रत्यक्ष करों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों द्वारा संसाधनों को जुटाना है भारत में संसाधन जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कराधान है।

b. सार्वजनिक बचत: सरकारी खर्च में कटौती और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिशेष में बढोत्तरी के द्वारा इन संसाधनों को सार्वजनिक बचत के माध्यम से जुटाया जा सकता है।

c. निजी बचत: सरकार निजी क्षेत्रों को बांड जारी करके , ट्रेजरी बिल, व्यक्तिगत ऋण इत्यादि के माध्यम से आम लोगो के पास रखी बचतों को बाजार में लाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है ।

2. आय और धन की असमानताओं में कटौती: राजकोषीय नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय असमानताओं को कम कर बराबरी या सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर की दर गरीब लोगों की तुलना में अमीर लोगों के लिए अधिक होती है । सेमी लक्जरी और लक्जरी वस्तुएं जिनका उपयोग ज्यादातर उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग द्वारा किया जाता है, पर अप्रत्यक्ष करों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। समाज में गरीब लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण अनुपात के रूप में सरकारी निवेश किया है।

3. मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण: राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और कीमतों को स्थिर रखना इसलिए, सरकार का हमेशा यह लक्ष्य रहता है कि राजकोषीय घाटे को कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए और नई बचत योजनाओं की शुरुआत कर वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए।

4. रोजगार सृजनः प्रभावी राजकोषीय उपायों के माध्यम से सरकार देश में रोजगार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। छोटी औद्योगिक (एसएसआई) इकाइयों पर कम कर और शुल्क लगाने से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और इसके परिणामस्वरूप अधिक रोजगार उत्पन्न होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार योजना द्वारा तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा रहाहै।

5. संतुलित क्षेत्रीय विकासः सरकार द्वारा देश में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है जिनमें नदियों में बाधों का निर्माण, बिजली, स्कूलों, सड़कों, औद्योगिक परियोजनाओं आदि का निर्माण। इन सभी को सार्वजनिक व्यय की मदद से किया जा रहा है।

6. भुगतान संतुलन में घाटे को कम करनाः कभी-कभी सरकार देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती है। उसी तरह आयात को रोकने के उपायों को भी अपनाया जाता है। इस प्रकार इन संयुक्त उपायों के माध्यम से देश के भुगतान संतुलन में सुधार होता है।

7. राष्ट्रीय आय में बढोत्तरीः यह राजकोषीय नीति की ताकत है कि इसमें अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम लाने की शाक्ति होती है। जब सरकार देश की आय में वृद्धि करना चाहती है तो सरकार देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि कर देती है। इसी तरह कुछ अन्य उपाय भी है, जैसे- कर दरों में कमी ताकि अधिक से अधिक लोग वास्तविक कर जमा करने के लिए प्रेरित हो सकें ।

8. बुनियादी ढांचे का विकासः जब सरकार लोगों के कल्याण हेतु रेल, स्कूलों, बांधों, बिजली, सड़क जैसी परियोजनाओं पर पैसा खर्च करती है तो इससे देश के बुनियादी ढांचे में सुधार होता है। एक बेहतर बुनियादी ढांचा देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने की कुंजी है।

9. विदेशी मुद्रा आयः जब देश की केंद्र सरकार घरेलू बाजार में चीजों के उत्पादन के अलावा कस्टम ड्यूटी में छूट, उत्पाद शुल्क में रियायत देती है तो इससे विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं जिससे देश में घरेलू निवेश बढ़ता है।

कोविड़-19 के लिए राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया (india) : -

एक अभूतपूर्व संकटकाल की पृष्ठभूमि में वर्ष 2020-21 राजकोषीय मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। आर्थिक गतिविधि में रुकावट के कारण राजस्व संग्रह में कमी, कमजोर लोगों, छोटे व्यवसायों, और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था पर महामारी के नतीजों को कम करने के लिए अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं ने उपलब्ध सीमित राजकोषीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बनाया। संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के ग्रॉस मार्केट बारोविंग के लक्ष्य को 7.8 लाख करोड़ रुपये के बजट आकलन से संशोधित कर 12 लाख करोड़ कर दिया गया।

इसलिए, भारत ने कई देशों द्वारा अपनाए गए फ्रंट-लोडेड बड़े प्रोत्साहन पैकेज के विपरीत अर्थव्यवस्था की उभरती स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त एक अंशांकित दृष्टिकोण अपनाया। भारत की राजकोषीय नीति ने इस समझ को प्रतिबिंबित किया कि कुल ऐग्रिगेट मांग, विशेष रूप से गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए, बचत करने के लिए एहतियाती उद्देश्यों को दर्शाती है, जो समग्र अनिश्चितता अधिक होने पर अनिवार्य रूप से ज्यादा होता है। इसलिए, महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान जब अनिश्चितता अधिक थी और लॉकडाउन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, भारत ने विवेकाधीन खपत/उपभोग को बढ़ाने की कोशिश में कीमती वित्तीय संसाधनों को बर्बाद नहीं किया। इसके बदले, नीति ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण/ ट्रान्सफर, छोटे व्यवसायों के लिए आपातकालीन

बनी रहती है | इतनी बड़ी आश्रित जनसंख्या भी राज्य की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ ही है |

पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव :-

- जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इससे भूमि जल , वृक्ष व पशु जगत के संतुलन बिगड़ते है और प्रदूषण की समस्या गंभीर होती है |

मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम :-

1. संसाधनों पर बढ़ता प्रभाव –

- जन घनत्व में वृद्धि
- प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में कमी
- जल उपलब्धता में कमी

2. सामाजिक आर्थिक विकास में कमी –

- निर्भरता अनुपात में वृद्धि
- स्वास्थ्य सेवाओं में कमी
- शिक्षा \ साक्षरता में कमी
- आवास की कमी

3. अन्य परिणाम –

- लिंगानुपात में विषमता
- गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि
- विकास कार्यों में बाधा
- पर्यावरण असंतुलन अपराधों में वृद्धि
- भौतिकवादी संस्कृति का प्रसार
- आर्थिक विषमता

अध्याय -16

मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास

- मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है |
- मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है ईंधन, खनिज, कृषि और जैव विविधता आदि |
- मध्य प्रदेश देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य भी है राज्य में हीरा उत्पादन 2019 – 20 में 25,603 हजार टन तक पहुँच गया |
- वर्तमान कीमतों पर , मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2019 – 20 के लिए 9.07 ट्रिलियन रहा | राज्य का GSDP 2015 -16 और 2019 – 20 के बीच 13.78% के CAGR (रुपये के संदर्भ में) में बढ़ा |
- मध्य प्रदेश का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) लगभग 2019 – 20 में 8.27 ट्रिलियन (USA $ 4117 .32 बिलियन) 2015 – 16 और 2019 – 20 के बीच , राज्य का NSDP लगभग 14.21% CAGR में बढ़ा |
- मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 109372 रु. है |
- मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (BPL POPULATION) 31.65% है|
- 2020 – 21 के लिए राजस्व घाटा 17514 करोड़ GSDP का 1.8 % पर लक्षित है |
- 2020 – 21 के लिए राजकोषीय घाटा 47360 करोड़ रुपये GSDP का 4.9 % पर लक्षित है |
- 2018 – 19 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.5 % थी जबकि देश 5.8 % थी |
- 2020 – 21 में मध्य प्रदेश में शिक्षा , खेल कला और संस्कृति क्षेत्र (33,408 करोड़ रुपये) की ओर सबसे अधिक आवंटन किया गया है |
- 2020 – 21 के लिए कुल व्यय 200343 करोड़ रुपये होने का अनुमान है |
- 2020 – 21 के लिए कुल राजस्व प्राप्ति 1,36,596 करोड़ रुपये होने का अनुमान है |
- मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से राष्ट्र के 8 प्रमुख खनिज राज्यों में से एक है|
- मध्य प्रदेश भारत का चौथा सबसे खनिज समृद्ध देश है (प्रथम तीन – 1. पश्चिम बंगाल 2. झारखंड 3. उड़ीसा |
- मध्य प्रदेश में प्रति 100000 व्यक्तियों पर उद्योगों की संख्या 5.24 है |

- मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2019 – 20 में 24% है |
- मध्य प्रदेश ने 2019 – 20 में कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 35%, 24% , और 41% अर्थव्यवस्था में योगदान दिया इन क्षेत्रों में क्रमशः 7.7% , 4.6% और 8.1 % की वृद्धि हुई |
- मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स (EASE of DOING INDEX) 2020 में चौथे स्थान पर है (1. आंध्र प्रदेश 2. उत्तर प्रदेश 3. तेलंगाना)

राज्य का आर्थिक वर्गीकरण :-

- मध्य प्रदेश के जिलों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित तथा पिछड़े जिलों की श्रेणी में बाँटा गया है -
- प्रदेश के 5 जिलों को विकसित जिला माना गया है, जबकि शेष को पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया है |

1. **औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिले** – भोपाल , ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, तथा कटनी |
2. **पिछड़े जिले (क श्रेणी)** - देवास, होशंगाबाद, खंडवा, मंदसौर , मुरैना, तरलाम , शहडोल , उज्जैन, विदिशा , सतना , नीमच , हरदा , श्योपुर |
3. **पिछड़े जिले (ब श्रेणी)** – बैतुल , सीहोर
4. **पिछड़े जिले (स श्रेणी)** – बालाघाट, छतरपुर , दमोह , दतिया , धार , गुना , झाबुआ , खरगौन , बड़वानी , मंडला , डिंडोरी , नरसिंहपुर , पन्ना , रायसेन , राजगढ़ , रीवा , शाजापुर , आगरा , मालवा , अलीराजपुर , सिंगरौली , अनुपपुर , निवाड़ी |

- इसके अलावा राज्य में देवास ,इंदौर , पीथमपुर , मंडीदीप और मालपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में 280 से अधिक Farmaceutical unit संचालित है |
- मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नोडल एजेंसी (मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) है |
- यह mega ifrastructure परियोजनाओं के समन्वय, सक्रियण , और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का केंद्र बिंदु है |
- मध्य प्रदेश समुंद्री उत्पादों और पेट्रोलियम उत्पादों सहित दो प्रमुख वस्तुओं का निर्यात करता है |
- FY 21 में (नवम्बर 2020 तक) मध्य प्रदेश में कुल दवा निर्माण , जैविक उत्पाद निर्यात का USA $ 947.86 मिलियन का निर्यात किया गया जो कुल निर्यात का 24% था |
- DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE (DIPIIT) के अनुसार अक्टूबर 2019 और सितम्बर 2020 के बीच मध्य प्रदेश में FDI प्रवाह 225.70 मिलियन अमेरिकी डॉलर था |
- 2020 में मध्य प्रदेश में रीवा सौर ऊर्जा परियोजना (NEW 750 M \W SOLAR POWER PLANT) एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था |

मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग :-

- मध्य प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है | कृषि प्रधान वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है |
- औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7 वाँ स्थान है |

मध्य प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किये है –

1. पीथमपुर (धार)
2. मेघन (झाबुआ)
3. मनेरी (मंडला)
4. मुरैना (पन्ना)
5. पीलुखेड़ी (राजगढ़)
6. मालनपुर (भिंड)
7. प्रतापपुर (टीकमगढ़)
8. बेदन (सीधी)
9. बोरे गाँव (छिंदवाड़ा)
10. किरनापुर (बालाघाट)
11. अमानपुरा (दमोह)
12. चेनपुरा (गुना)
13. करोंदरा (शिवपुरी)
14. बडेरा (दतिया)
15. चंद्रपुर (छतरपुर)
16. बंडोल (सिवनी)
17. बगसपुर (नरसिंहपुर)
18. मंडीदीप (रायसेन)
19. सिंदगवा (सागर)
20. रीवा (रीवा)

- इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक जिला है।
- मध्य प्रदेश में 513 सूती कपड़े के कारखाने है ।
- प्रदेश में सूती कपड़े के अधिकांश कारखाने पश्चिमी भाग में केंद्रित है जिसमें इंदौर , उज्जैन प्रमुख है । राज्य में प्रथम सूती कारखाना 1906 में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी ।

कृत्रिम रेशे के कपड़े का उद्योग :-

- मध्य प्रदेश के नागदा में कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने के कारखाना है । साथ ही कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने के कारखाने, इंदौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन एवं देवास में भी है ।

वनस्पति घी :- मध्य प्रदेश के गंजबासौदा (विदिशा) जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर, सहित वनस्पति घी बनाने के 10 कारखाने है ।

रेशम उद्योग :- प्राकृतिक रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1984 में रेशम संचनालय की स्थापना की गई । इस उद्योग के विकास के लिए शहतूत की खेती को प्रोत्साहित किया गया ।

- मंडला प्रमुख रेशम उत्पादक जिला है ।

सोयाबीन तेल उद्योग :-

- मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है ।
- राज्य में सोयाबीन तेल निकलने के लिए सालवेंट एक्स्ट्रेक्ट प्लांट लगाये गये है ।
- मध्य प्रदेश इंदौर , उज्जैन , बडवाह में सोथा प्लांट है ।

चावल मिले :-

छतीसगढ़ में है, तथापि कुछ मिल इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा में भी स्थापित है । यहाँ धान से चावल निकला जाता है ।

दाल मिले :- मध्य प्रदेश के इंदौर , उज्जैन , भोपाल एवं सागर में दाल मिले है ।

स्ट्रा बोर्ड मिल :- शाजापुर में कृषि अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग कर स्ट्रा बोर्ड बनाया जाता है ।

ऑइल मिले :- मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सरसों से तेल निकालने का एक कारखाना स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 25 लाख टन सरसों प्रतिदिन पिराई जाती है ।

मध्य प्रदेश के कृषि उद्योग विकास के उद्योग :-

कीटनाशक सयंत्र , बीना :-

10 हजार टन पाउडर , एक लाख लीटर तरल कीटनाशक औषधियों का निर्माण करता है ।

जीवाणु खाद्य संयंत्र :- भोपाल

- फल सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई भोपाल ।
- दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र - होशंगाबाद ।

मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग :-

- वन बाहुल्य छत्तीसगढ़ अंचल के पृथक हो जाने के बावजूद मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से सम्पन्न राज्य है ।
- यद्यपि मध्य प्रदेश में वनों का वितरण असमान है ।
- मध्य प्रदेश में देश का सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन है , जिसमें विभिन्न किस्मों की इमारती एवं जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है ।
- मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग धंधे निम्न है -

1. कागज उद्योग :-

- **1948 - 49** में नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल , नेपानगर (जिला बुरहानपुर) तथा ओरियंटल पेपर मिल , अमलाई (अनुपपुर) की स्थापना के बाद मध्य प्रदेश में कागज उद्योग को एक नई दिशा मिली ।
- इसके अलावा भोपाल , रतलाम एवं ग्वालियर में भी कागज बनाया जाता है ।
- इंदौर में महीन कागज तथा होशंगाबाद में नोट बनाने का कागज तैयार किया जाता है ।
- नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 88 हजार मैट्रिक टन है इस कारखाने में अखबारी कागज का उत्पादन हुआ था ।
- बिड़ला द्वारा स्थापित अमलाई का कारखाना अनुपपुर से कुछ दूर कटनी बिलासपुर रेलवे मार्ग पर स्थित कारखाने को बुढार खदान से कोयला दिया जाता है इस कारखाने में 90 % पुस्तक छपने योग्य व लिखाई योग्य कागज बनता है ।
- मध्य प्रदेश ने कागज उद्योग में वनों के उत्पादन का समुचित उपयोग कर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए रोजगार में बढ़ोतरी की है ।

2. बीड़ी उद्योग :-

- मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । यहाँ तेंदुपत्ता कई मजदूर परिवार के जीविकापार्जन का साधन है ।

- तेंदुपत्ता से मजदूर फुरसत के साथ बीड़ियाँ बनाते हैं। इस व्यवसाय में न केवल पुरुष , बल्कि बूढ़े , महिलाएँ व बच्चे भी संलग्न हैं।
- मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने के लगभग 250 – 260 कारखाने हैं इसका मुख्य केंद्र जबलपुर में है।

3. लकड़ी चीरने का उद्योग :-

- मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने के व्यवसाय भी काफी प्रचलित है।
- प्रदेश में लकड़ी चीरने के 113 कारखाने हैं यहाँ इमारती लकड़ी के बड़े – बड़े लट्ठे लाये जाते हैं।
- इसके कारखाने मुख्यतः मध्य प्रदेश के जबलपुर , मंडला , बालाघाट , छिंदवाड़ा में है लेकिन मुख्य केंद्र जबलपुर है।

4. कत्था उद्योग :-

- मध्य प्रदेश में खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी तथा बानमौर में है।
- यहाँ पर खैरवार जनजाति द्वारा कत्था बनाने का कार्य किया जाता है।

5. मधुमक्खी पालन :-

- मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद तथा मोम प्राप्त होता है।
- प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी जिलों में शहद का अच्छा उत्पादन रहा है सबसे अधिक शहर मुरैना जिले से प्राप्त है।

6. प्लाईवुड उद्योग :-

- मध्य प्रदेश प्रथम प्लाईवुड कारखाना 1964 इटारसी में स्थापित किया गया था।
- छिंदवाडा एवं कोसयी , बैतुल में प्लाईवुड तथा नक्काशीदार लकड़ी का कारखाना है।

7. लाख उद्योग :-

- लाख एक प्राकृतिक रेजिन होता है जो केरिया लवका नामक कीट द्वारा स्त्रावित होता है।
- राज्य में कच्चे लाख से सीड लाख तथा शैलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना उमरिया में है।

8. चिप एवं माचिस डिब्बी उद्योग :-

- चिप बोर्ड एवं पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना इटारसी में तथा माचिस की डिब्बी बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थापित है।

अन्य प्रमुख उद्योग :-

विदेशी सहायता से निर्मित प्रमुख उद्योग –

1. **भेल (bhel)** – इसकी स्थापना 1964 में ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में की गई थी तथा 2013 में महारत्न कम्पनी का दर्जा दिया गया था।
(BHEL – BHART HEAVY ELECTRICAL LIMITED)

2. **OPTICAL FIBER FACTORY (OPTICAL फाइबर कारखाना):-**
इसकी स्थापना मंडीदीप रायसेन में जापान की सहायता से की गई है।

3. **NATIONAL FERTILIZER FACTORY :-**
इसकी स्थापना 1984 में विजयनगर गुना में अमेरिका और इटली के सहयोग से की गई है।

4. **तेल शोधक कारखाना :-**
इसकी स्थापना 2008 में बीना के आसागोद में ओमान की सहायता से की गई है।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सार्वजनक क्षेत्र के उद्योग:-

रक्षा मंत्रालय –

गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री , खमरिया , जबलपुर इसकी स्थापना 1943 में की गई थी यहाँ युद्धोपकरण निर्मित किए जाते है।

I. गन कैरिज फैक्ट्री – इसकी स्थापना 1943 में जबलपुर में की गई यहाँ भी युद्धोपकरण निर्मित किए जाते है।
II. हैवी व्हीकल फैक्ट्री वाहन – इसकी स्थापना जबलपुर में 1955 – 66 में की गई इसमें रक्षात्मक एवं भारी व्यवसायिक वाहन बनाए जाते है।
III. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री – इसे इंटिग्रेटेड गाडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत 1969 – 70 में स्थापित किया गया था।
IV. गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री – यह कटनी में स्थापित किया गया था इसमें युद्धोपकरण निर्मित किए जाते है।
V. ग्रे आयरन फाउण्ड्री – ये जबलपुर में है इसमें कच्चे लौह का प्रयोग किया जाता है।
VI. रेल मंत्रालय –

- **रेलवे कोच फैक्ट्री** – इसकी स्थापना 1975 – 76 में निशातपुरा भोपाल में की गई। यहाँ रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है।

सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले :-

	जिला	प्रतिशत
1.	छतरपुर	42.6
2.	शिवपुरी	42.0
3.	बुरहानपुरी	36.8
4.	अशोकनगर	35.6
5.	खंडवा	34.0

न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय दर वाले जिले :-

	जिले	प्रतिशत
1.	मंदसौर	11.5
2.	भिंड	8.8
3.	उज्जैन	8.5
4.	शाजापुर	7.2
5.	सागर	13.0

मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एवं उनकी उपजातियाँ

क्र. सं.	जनजातियाँ	उपजनजातियाँ	निवास स्थल
1.	गोंड	परधान , अगरिया , ओझा	प्रदेश के सभी जिलों मुख्यतः नगारची, सोलहास विंध्य और सतपुड़ा अंचल में
2.	**भील**	बरेला , भिलाला,पटरिया, रैथास	धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी
3.	बैगा	बिंझवार, नरोतिया, भतोरिया, नागर, राय, मैना	मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर
4.	कोरकू	भोवासी, रूम,बवारी, बोडोया	खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाडा, देवास
5.	भारिया	भूमिया, भुईहार,पंडा	छिंदवाडा, जबलपुर, मंडला, शहडोल, सीधी, पन्ना
6.	माड़िया	अबुझमाडीया, दंडामी, मोडिया, मेटाकोईतुर	जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना, छिंदवाडा, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, राजगढ़
7.	सउर	छतरपुर, टीकमगढ़,सागर	पन्ना, दमोह
8.	अगरिया		मंडला ,डिंडोरी, सीधी, शहडोल , सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट , बैतुल
9.	कोल	रोतिया , रौतेले	रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनुपपुर
10.	परधान		सिवनी , छिंदवाडा , बालाघाट, बैतुल ।
11.	खैरवार		सीधी, सिंगरौली, अनुपपुर, शहडोल, पन्ना, छतरपुर

जनजाति अनुसन्धान संस्थान (भोपाल)-

- जनजाति के पूर्ण विकास हेतु राज्य सरकार ने 1954 में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना छिंदवाडा में की थी ।
- 1965 में इसका स्थानान्तरण भोपाल कर दिया गया।
- इसका उद्देश्य जनजातियों के जीवन संस्कृति , आर्थिक तथा शैक्षणिक प्रवृतियों का अध्ययन प्रवृतियों का संरक्षण करना।

अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु संस्थाएँ :-

- मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 को गठित किया गया था ।
- मध्य प्रदेश के आदिवासी वित्त एवं विकास निगम 1994 को गठन किया गया था ।
- मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग 1995 को गठत किया गया था ।
- जनजाति संग्रहालय भोपाल 6 जून 2013 ।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/dy0fu7

Online order - https://bit.ly/3BGkwhu

Call करें - 9887809083